भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 587

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां**

**587. श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी :**

**श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 61 संस्वीकृत पदों में से केवल 29 न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा न्यायाधीशों के 32 पद रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) मंत्रालय इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए क्या प्रयास कर रहा है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** तारीख 01.12.2018 को तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की स्वीकृत पद संख्या 61 है जिसके जिसके मुकाबले में उच्च न्यायालय में 33 रिक्तियों को छोड़कर कार्यरत पद संख्या 28 है । रिक्तियों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतया और एक समयबद्ध रीति से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, रिक्तियां न्यायधीशों की सेवानिवृति, पदत्याग और उन्नयन के कारण उद्भूत होती रहती हैं । उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, प्रस्ताव संबंद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया जाना है। हाल ही में, सरकार को हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त किया है जिसमें उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 14 नामों (07 अधिवक्ताओं और 07 न्यायिक अधिकारियों) की सिफारिश की गई है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*